ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

केनाइन डिस्टेंपर रोग से मर रहे हैं गिर वन के शेर

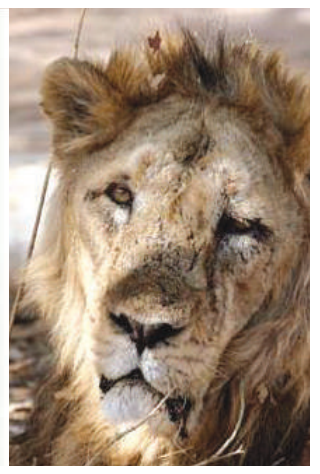

रविवारीय, 14 - 20 जून 2020 वर्ष- एक, अंक-45, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

खनिज नीलामी को 6 से 9 माह के लिए आगे बढ़ाएं:मुख्यमंत्री

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिख आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनी भाग नहीं ले सकेंगी। घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा।

सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन भी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पूर्व राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है। सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता भी है।

रांची शहर के कई हिस्सों में दिसंबर में जो नालियां बननी शुरू हुईं वो आज तक ढकी नहीं गयी हैं, कई इलाकों में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना था , पर उन्हें ओवरहेड ही लगा दिया गया, रातू रोड के कब्रिस्तान और पंडरा पुल से पहले का इलाका बरसात में तालाब बन जाता है करोड़ो फूंकने के बाद भी यहां जलन निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया ऐसे में घनघोर बारिश होने पर आम लोगों को कष्ट झेलने होंगे और दुर्घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रांची में उफनते नालों में गिर कर कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं।

रांची शहर के वार्डों में अधूरी पड़ी नालियां, जल निकासी के नालों का अतिक्रमण, कोविड-19 के बीच बरसात में संक्रमण का खतरा ऐसे में

क्या गुल खिलायेगा मॉनसून ?

मुख्य संवाददाता

रांची : राजधानी में प्रीमॉनसून की एकदिनी बारिश ने ही यह अहसास करा दिया है कि मॉनसून के शबाब पर होने के बाद रांची की क्या दुर्गति होने वाली है। महज एक दिन की घंटे भर की तेज बारिश में ही शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कें तालाब में मब्दिल हो गयीं थीं। ये हाल तब है जब पिछली सरकार ने पूरे रांची में नालों के निर्माण पर खूब पैसे बहाये थे और राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब दिखाया था। उस दरम्यान करोड़ो की लागत से वहां भी नाले बने जहां उसकी जरूरत नहीं थी और वहां अब तक नहीं बने जहां जल निकासी के लिये नाले की सख्त जरूरत थी।

वैश्विक लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर घटा है। रांची में इस बार एक दो दिनों के लिये दो दशक पुराना मौसम भी देखने को मिला जब गर्मी बढने पर यहां नॉर्वेस्टर के बादलों के बनने से तेज बारिश हो जाया करती थी। ये सारे लक्षण बता रहे हैं कि रांची को इसबार के मॉनसून में जोरदार बारिश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रांची इसके लिये पूरी तरह से तैयार नहीं है।

राजधानी बनने से पहले रांची में आवासों अपार्टमेंटों की संख्या कम थी बाद में अतिक्रमण से अवैध मकानों और कॉलोनियों की बाढ़ आ गयी। और तेज बारिश में पानी के निकलने के रास्ते बंद होते गये। यहीं कारण है कि जहां पहले रांची की बारिश लोगों को एक खुशनुमा अहसास कराती थी वही अब एक सरदर्द बन कर आती है।

नब्बे के दशक में एक साल रांची में चेरापुंजी से भी ज्यादा बारिश हुई थी। उस साल हर रोज दो से तीन घंटे घनघोर बारिश हुई थी। उसके बावजूद रांची में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन इस साल मॉनसून को रांची कितना झेल पायेगी? नारकीय स्थिति से कैसे बचेगी? ये तो आसन्न मॉनसून ही बतायेगा।

नदी नालों के अतिक्रमण का खामियाजा भुगतते हैं लोग

बरसात में शहर की दुर्गति का एक और कारण यहां के उन नदी नालों का अतिक्रमण है जिनसे होकर पहले तेज बारिश में भी पानी की निकासी होती थी। पिस्का मोड़ से आगे बसा पंचशील नगर बरसात के मौसम में जलमग्न हो जाता है। यहां के ज्यादतर मकानों के नीचले तल्ले में पानी भर जाता है। दरअसल पूरा पंचशील नगर ही एक छाटी नदी के ऊपर बसा हुआ है यह नदी पहले इस इलाके से पानी को लेकर अंततः कांके डैम में मिल जाती थी जिसे भूमाफियाओं ने भर कर बेच दिया। संभव है ऐसा ही वाकया रांची के कई ईलाकों में हो जहां नदी नाले पर ही घर बने हुये हैं।

कोविड-19 काल में बीमारियों से संक्रमण का खतरा दुगुना होगा

बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियों के संक्रमण का खतरा वैसे भी बढ़ जाता है। क्योंकि धूप और नमी से वायरस तेजी से पनपते हैं और इनके फैलने का माध्यम बहुतायत में उपलब्ध होता है। यही कारण है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मौसम में मांसाहार से लेकर बहुत सारी साग सब्जियों को खाने से परहेज किया जाता है। हकीकत में तो बरसात का मौसम सबसे ज्यादा परहेज का होता है। इस बार खतरा दुगुना है क्योंकि विश्व पहले से ही कोविड-19 वायरस के खतरे से जूझ रहा है ऐसे में रांची में नालों की दुर्दशा और जल निकासी की कुव्यवस्था मॉनसून में स्थिति को और बिगाड़ सकती है?

झारखंडी कामगारों ने अपनी अलग पहचान बनाई है: मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका रेलवे स्टेशन से झारखंड के कामगारों के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के द्वारा देश के कठिन व दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में राज्य के कामगार अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के कामगार शुरू से ही देश के हित और विकास में अहम योगदान देते आ रहे हैं ' कोरोना काल में एक बार फिर वे देश के दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में अपना योगदान करने के लिए जा रहे हैं ' जहां सामान्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है । लेकिन झारखंड के कामगारों ने अपने कार्य से पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन से कहा कि वे कामगारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें झारखंड के कामगार अग्रणी भूमिका निभाएंगे ' इसके लिए कामगारों का पहला दल लद्दाख भेजा जा रहा है और अगले कुछ दिनों में हजारों कामगार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्य में योगदान करने के लिए रवाना होंगे ।

लद्दाख में सड़क निर्माण के लिये कामगारों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा किया रवाना

सीमा सड़क संगठन को झारखंड के कामगारों की नियुक्ति में पारदर्शिता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मजदूरी आदि को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ।कामगारों का शोषण नहीं हो , इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया जा रहा है और सभी कामगारों का पता और मोबाइल नंबर भी रखा गया है ताकि उनकी जानकारी समय-समय पर सरकार को मिलती रहे ।इस मौके पर श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक नलिन सोरेन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, सीमा सड़क संगठन के अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार, दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा व अन्य मौजूद थे।

टांड़ खेत में धान की सीधी बुआई करें : धान विशेषज्ञ

डॉ कृष्णा प्रसाद

- **30 जुन तक टांड़ खेत में धान की सीधी बुआई पूरी करें**
- **कम लागत में आसानी से अधिकतम शुद्ध लाभ**
- **खरपतवार बड़ी समस्या, खरपतवारनाशी का प्रयोग जरूरी**

रांची : राज्य की करीब 28 लाख हेक्टेयर भूमि में खरीफ फसलों की खेती मॉनसून की वर्षा पर निर्भर है. वर्ष 2018-19 में प्रदेश के करीब 15.27 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती हुई. धान की खेती के लिए मध्यम भूमि दोन (दो) और निचली भूमि दोन (एक) काफी उपयुक्त होती है. अधिकतर भूमि में धान के बिचड़ों की रोपाई की जाती है. जिसमें अधिक श्रम, खर्च, सिंचाई एवं समय लगता है. रबी फसलों की बुआई में देरी हो जाती है. जबकि धान की सीधी बुआई तकनीक में इनपुट की कम मांग, श्रम की बचत एवं कम पानी की आवश्यकता होती है. फसल की कम परिपक्वता अवधि, कम उत्पादन लागत व अधिकतम शुद्ध लाभ की वजह से यह पुनः लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है. धान की सीधी बुआई एक बहुत पुरानी विधि है,जो वर्तमान में राज्य के पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले में काफी प्रचलित है. जहाँ टांड़, मध्यम भूमि दोन (दो) एवं निचली भूमि दोन (एक) में इस विधि से धान की खेती की जाती है. जबकि अन्य जिलों के टांड़ भूमि में सीमित रूप से धान की खेती सीधी बुआई की जाती है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित आईसीएआर - अखिल भारतीय समन्वित धान अनुसंधान परियोजना अधीन किसानों के खेतों में धान की रोपाई एवं धान की सीधी बुआई के तुलनात्मक अध्ययन के प्रत्यक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं. परियोजना अन्वेशक डॉ कृष्णा प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद के मार्गदर्शन में धान के 4 उन्नत किस्मों बिरसा विकास -1, बिरसामति, आईआर - 64 की सूखा रोधी किस्म तथा वीवीडी -111 किस्म की सीधी बुआई और रोपा वाले धान के खेतों में फसल स्थिति और उपज लगभग एकसमान पाया गया है.

डॉ प्रसाद ने हाल में हुए वर्षा का लाभ लेते हुए किसानों को ऊपरी (टांड़) जमीन में 15 से 30 जुन तक धान सीधी बुआई करने की सलाह दी. इसमें बुआई से पहले खेतों में 2 टन प्रति एकड़ की दर से सड़ी गोबर खाद या कम्पोस्ट खेतों में बिखेर कर अच्छी तरह से जुताई करने तथा दीमक से बचाव के लिए नीम या करंज की खल्ली 200 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत में डालने को कहा है. धान की अनुशंशित उन्नत किस्मों में बिरसा विकास - 111, बिरसा धान - 108, बिरसा विकास धान - 109, बिरसा विकास धान - 110 तथा वंदना का प्रयोग करने को कहा. छिटकवाँ विधि में 40 किलो तथा हल के पीछे 30 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है. बीज को 250 ग्राम थीरम या 200 ग्राम बैबिस्टीन से उपचारित करने के बाद ही बुआई किया जाना चाहिए. उर्वरकों में 52 किलो यूरिया, 75 किलो एसएसपी तथा 15 किलो पोटाश या 42 किलो यूरिया, 26 किलो डीएपी एवं 15 किलो पोटाश उर्वरक प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें. डीएपी एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दें. यूरिया को दो भागों में बाँटकर बीज अंकुरण के 15 दिनों तथा 30 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग करें.

धान की सीधी बुआई की खेती में खरपतवार नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या होती है, जिससे फसलों को काफी हानी होता है ।... शेष पेज तीन पर

एसोचैम का नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट

खाद्य, कृषि और डेयरी - रिफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड

खाद्य, कृषि और डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19का प्रभाव पड़ा है। इन क्षेत्रों में नए सुधारों की आवश्यकता है और इसे ध्यान में रखते हुए एसोचैम ''फूड, एग्रीकल्चर एंड डेयरी'' - रिफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड पर नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट का आयोजन किया गया। यह आयोजन भरत जायसवाल, क्षेत्रीय निदेशक, एसोचैम द्वारा प्रस्तावना और स्वागत भाषण के साथ शुरू हुआ। अरुण कुमार सिंह, झारखंड सरकार में खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत और गैर पंजीकृत लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूरों को खाद्य अनाज उपलब्ध कराया गया है। निधि रसोई, दाल भात केंद्र आदि के नाम से 6000 सामुदायिक रसोई शुरू की गई हैं और लगभग 3.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार सृजन और राज्य में नए निवेश के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

इस अवसर पर प्रदीप हजारी, विशेष सचिव सह सलाहकार, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार ने विशेष संबोधन दिया।नितिन कुमार चौधरी, लिवो हेल्थ केयर प्रा. लि. और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए।

बड़ा तालाब क्या फिर शुरू हुआ सफाई का प्रहसन ?

मनोरंजन सिंह

जलकुंभी से पटे इस तालाब की सफाई मॉनसून के बिल्कुल सर पर सवार होने पर ही सबों को सूझी है? गर्मियों में जब पानी कम था और शुष्क मौसम में यहां से जलकुंभियों को हटाना आसान था तब किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया । 13 अक्टूबर 2019 अंक में ग्रीन रिवोल्ट ने इसके इतिहास और साफ सफाई पर अंक विशेष प्रकाशित किया था।

रांची : बड़ा तालाब से जलकुंभी हटाने का काम फिर से शुरू हुआ है। इसमें आम लोगों से हाथ बंटाने का आह्वान रांची की मेयर ने किया है। रांची के पुराने बाशिंदे यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रांची के बीचोबीच बने इस विशाल तालाब की साफ सफाई और संवारने का प्रहसन सालों से चलते रहता है। लेकिन तालाब आज भी स्वच्छ और सुंदर नहीं बन पाया। इसके टापू पर स्वामी विवेकानंद की विशाल मुर्ति लगा कर , पुल बना कर कर्नल ऑस्ले के बनवाये इस तालाब का नाम विवेकानंद सरोवर तो कर दिया गया, पर तालाब के स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसका पानी प्रदूषित है, संवारने के नाम पर ठेकेदारों इंजीनियरों ने इसके चारो और इस तरह से दिवार बना दी है कि उसमें बरसात का पानी एकत्र नहीं होता?

दरअसल बड़ा तालाब के जलकुंभी से छा जाने का ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी यह तालाब जलकुंभियों से ढकता रहा है और सबसे बुरी हालत तब हो जाती है जब ये जलकुंभी सड़ कर पानी को भयंकर बदबूदार बना देता है। कांके डैम में भी उसके फाटक के पास कुछ ऐसा ही होता है आज जिस रफ्तार और मौसम में यहां जलकुंभी निकाला जा रहा है उससे तो यही लगता है कि इसकी सफाई होगी भी नहीं तब तक तेज बारिश शुरू हो जायेगा। यानि सफाई का प्रहसन फिर से चालू है?

विलुप्त हो रही नई प्रजातियों को बचाने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी

एजेंसियां

आने वाले दशकों में आगे की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इसलिए, विलुप्त होने के खतरे को कम करना बहुत जरूरी है

जैव विविधता को लगातार नुकसान हो रहा है, इसको बचाने के लिए अब तक हुए वैश्विक समझौते भी अधिक सफल नहीं रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नुकसान पर रोक लगाने के लिए विज्ञान आधारित कार्रवाई होनी चाहिए। जैव विविधता को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन और तापमान पर नियंत्रण भी जरूरी है।

प्रस्तावों में संरक्षण विशेषज्ञ प्राकृतिक दरों से प्रजातियों के विलुप्त होने को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य का सुझाव दिया गया है, जिसमें एक वर्ष में कम से कम 20 विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाने का उद्देश्य है। यह पेपर साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। संरक्षण सभी प्रमुख प्रजातियों पर लागू होगा जो कि प्रमुख वर्गीकरण समूहों (कवक, पौधे, अकशेरुकी और कशेरुक) और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें ताजे पानी, समुद्री और स्थलीय शामिल हैं।

यूसीएल सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट रिसर्च के सह-अध्ययनकर्ता प्रोफेसर डेम जार्जिना मेस ने कहा जैव विविधता के नुकसान को रिकॉर्ड करने के कई तरीके हैं लेकिन विलुप्त होना अलग है। एक बार एक प्रजाति का नुकसान होता है, तो यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।

जैव विविधता को बचाने के लिए दुनिया भर में योजनाएं बनाना आदि अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल है। इस संधि को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (सीबीडी) कहते हैं। इसके तहत 2020 के बाद जैव विविधता को बचाने के लिए इसके द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

2010 में, सीबीडी ने प्रकृति के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई थी, जिसमें वर्ष 2020 तक 20 समयबद्ध, मापने योग्य लक्ष्य रखे गए थे, जिसे एची जैव विविधता लक्ष्य कहते है। इनमें से,

केवल 4 में अच्छी प्रगति देखी गई है, 4 के बारे में स्पष्ट नहीं है जबकि 12, प्रकृति से संबंधित प्रवृत्तियां, काफी खराब हो गई हैं। सीबीडी की अगली बैठक में नए लक्ष्यों और लक्ष्यों पर सहमति को 2021 तक टाल दिया गया है। इन लक्ष्यों में जैव विविधता के लिए आवश्यक परिणामों पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। विशेषज्ञों ने कहा प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमें एक मजबूत जवाबदेही तंत्र बनाना होगा।

एक प्रजाति के कभी पूरा न होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक रूप से रक्षात्मक उपाय किए जाने की जरुरत है।

प्रोफेसर रिचर्ड ग्रेगोरी के अनुसार हमें प्रकृति को बचाने के लिए 'नॉर्थ स्टार' अर्थात आशा की किरण की आवश्यकता है। ताकि हम ऊपर और नीचे से जैव विविधता के नुकसान को कम कर सके, और हमारे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापना करके प्रजातियों की आबादी को पुनर्प्राप्त कर पाएं।

प्रोफेसर मार्क रौंसेवेल प्रमुख अध्ययनकर्ता ने कहा: आने वाले दशकों में ग्रह पर पड़ने वाले मानव दबाव के कारण आगे की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इसलिए, विलुप्त होने के खतरे को कम करना प्रमुख लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण नीति के आगे विकास में मदद की जरूरत है, पृथ्वी पर जीवन की हानि को कम करने में सरकारों का समर्थन सबसे बड़े साधन के रूप में है।

डॉ. माइक हरफुट ने बताया कि अगले दशक में जैव विविधता के नुकसान को कम करने और लोगों और प्रकृति के बीच बेहतर संतुलन खोजने के लिए समन्वय महत्वपूर्ण है। एक नई प्रजाति के विलुप्त होने से पहले उसको बचाने का प्रयास किया जा सकता है। दुनिया में प्रकृति संकट से निपटने के लिए सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

आत्मघाती अतिक्रमण

एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष पेयजल की उपलब्धता तेजी से घट रही है और भविष्य में देश जलसंकट से जूझेगा। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ अस्सी हजार से कुछ ज्यादा छोटे बड़े तालाब और झीलें हैं उनमें भी ज्यादतर तेजी से खत्म हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, और उनके जल संग्रह की क्षमता कम हो रही है। भारतीय भूमि में जल तेजी से अवशोषित हो जाता है, हमारे देश के मौसम में जल का वाष्पीकरण भी तीव्र है, बहुत सारी नदियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में जल संरक्षित होने के बजाय समुद्र में चला जाता है। इन कारणों से देश में जल की समस्या भविष्य में और गहरी होगी।

भारत में एक और आत्मघाती समस्या है। तालाबों झीलों को प्रदूषित और अतिक्रमित करने की। ये समस्या बहुत विकराल है। अतिक्रमण के प्रति लुंजपुंज रवैये के कारण रांची में कांके डैम के किनारे बहुत सारे अवैध मकान बना लिये गये, जमीन दलालों ने फर्जी कागजात बना कर लोगों को डैम की जमीन रजिस्ट्री कर दी, खरीददारों ने भी बिना जांच पड़ताल किये वैसी जमीन खरीद ली जो डैम का कैचमेंट था। यानि जहां बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। अब जब वर्तमान सरकार यहां सख्ती से अतिक्रमण हटाने का काम करने जा रही है तो गरीबों के आसियाने उजड़ जायेंगे और लोग कहां जायेंगे? जैसी आवाजे भी जरूर उठेंगी, पर अतिक्रमण करते समय उन्हें रोकने और समझाने का काम किसी ने नहीं किया। लोगों की ये प्रवृति ही आत्मघाती है। बेहतर हो कि सरकार इस बार अतिक्रमण हटाने के बाद यहां कोई पुख्ता बाड़ लगाये या निगरानी का कोई ऐसा इंतजाम करे कि कोई अवैध मकान दुबारा डैम की जमीन पर न बने।

झारखंड ही नहीं देश भर में ग्रीनलैंड और संरक्षित भूमि का अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। रांची में कांके डैम अतिक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है अमीर गरीब से लेकर भूमाफियाओं तक ने इसकी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया है।

डैम को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास कभी भी पुख्ता तौर पर नहीं हुआ है। उल्टे कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसके जमीन पर अवैध बस्तियां बसाने का ही काम किया ताकि एक सॉलिड वोट बैंक तैयार हो सके। राज्य में सरकारें भी अतिक्रमण के दरम्यान कान में तेल डाल कर सोयी रहती हैं और समस्या जब बड़ी हो जाती है तो एकाएक सख्ती से अवैध मकानों कॉलानियों को ढहाने का काम शुरू होता है और तब कहा जाता है कि गरीबों का आशियाना छिन गया?

लॉकडाउन में माफिया खोद रहे हैं नदियां

पिछले करीब तीन महीने के लॉकडाउन में उत्तराखंड में बेशक मंदिरों के कपाट से लेकर पर्यटन स्थल तक लॉक रहे हों, लेकिन इस दौरान यहां की नदियों में अवैध खनन खूब जोरों पर रहा। कहीं नदी की बीच धारा में बिना इजाजत पोकलैंड और जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें से उतार दी गई तो कहीं अवैध खनन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए। हालात ये हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट को इस मसले में राज्य सरकार और कई दूसरे संस्थानों से रिपोर्ट तलब करनी पड़ी है। उत्तराखंड में सुदूर थराली से लेकर कोटद्वार और हल्द्वानी तक से इन दिनों नदियों में अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। चमोली जिले में थराली के पास पिण्डर नदी की धारा में पोकलेन मशीन ही उतार दी ।

राज्य सरकार ने लॉकडाउन से पहले राज्यभर में विभिन्न नदियों में रेत-बजरी चुगान के ठेके दिये थे। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खनन में मशीनों की इस्तेमाल संबंधित जिला अधिकारी की इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन शुरू हो जाने के कारण सब कुछ बंद हो गया। नियमानुसार नदियों में इस दौरान खनन कार्य भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खनन लाइसेंसधारियों ने कई जगहों पर लॉकडाउन के दौरान ही जेसीबी और पोकलैंड मशीनें नदियों में उतार दी और आवंटित पट्टे की आड़ में कई बड़े क्षेत्र में रेत-बजरी का चुगान शुरू कर दिया गया। खास बात यह है कि 24 मार्च को ही नैनीताल हाई कोर्ट में बागेश्वर में अवैध खनन संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खनन कार्य में बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी।

अवैध खनन को लेकर जब स्थानीय मीडिया ने डीएम से पूछा कि लॉकडाउन में क्या उन्होंने जेसीबी और पोकलैंड मशीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी है तो डीएम का जवाब था कि यह अधिकार उन्होंने एसडीएम को सौंप दिया है। एसडीएम से पूछा गया तो उनका कहना था कि वे लॉकडाउन के कारण बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इस सवाल का बाद में जबाव देंगे।

किताबों और अखबारों का अंत नजदीक है?

अजित बालकृष्णन

कागज का उपयोग कम हो जाना पर्यावरण के नजरिये से तो एक ब्अच्छी खबर है। इससे कागज निर्माण के लिये पेड़ पौधों की कटाई में कमी आयेगी पर आज मीडिया और पुस्तकों के अस्तित्व पर संकट आन पड़ा है। और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि किताबों और समाचार पत्रों पर विलुप्ति का खतरा मंडराने लगे।

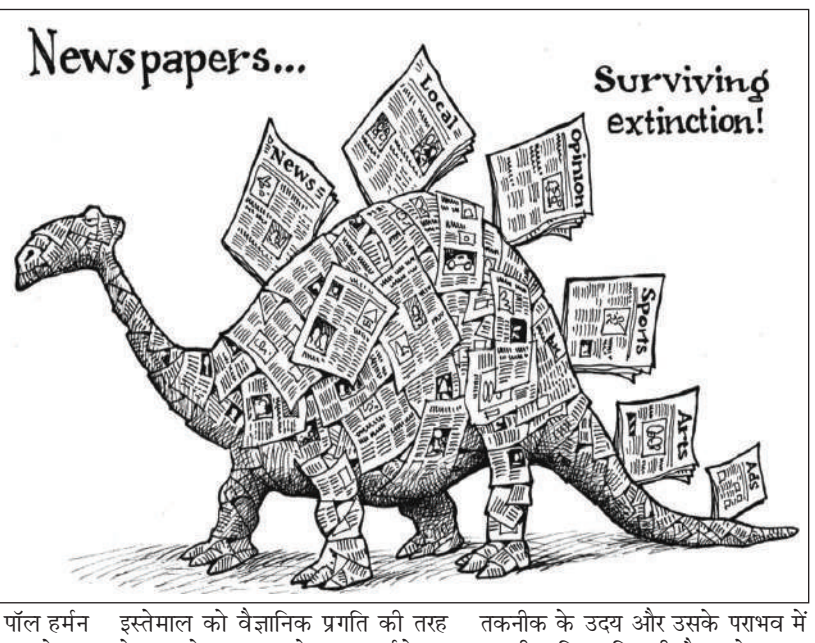

कई महीनों तक खिंचे लंबे लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में समाचार पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब सुबह की चाय के साथ अखबार या सप्ताहांत पर पत्रिकाओं या पुस्तकों का सहारा पहले जैसे नहीं मिल पा रहा। समाचार पत्र और पत्रिकाएं केवल घरों तक होने वाली आपूर्ति के भरोसे नहीं हैं बल्कि उनके लिए दुकानें और स्टॉल भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जहां से लोग इन्हें खरीदते हैं। इसके अलावा कई श्रेणियों में विज्ञापनदाता मसलन यात्रा क्षेत्र के विज्ञापनदाताओं को खुद राजस्व संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने विज्ञापन देने बंद कर दिए हैं। ये विज्ञापन हर प्रकार के मीडिया के लिए लेकिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए खासतौर पर महत्त्वपूर्ण हैं।

क्या सन 1990 के दशक के आखिर में इंटरनेट के आगमन के बाद से चला आ रहा प्रिंट मीडिया का कष्टप्रद सफर अब अपने अंत की ओर है? सन 1960 के दशक के आरंभ में जब नायलॉन और पॉलिएस्टर के कपड़ों का आगमन हुआ था और लोगों में पॉलिएस्टर की पैंट और नायलॉन की साड़ियां खरीदने की होड़ मची थी तब ऐसा लगा था मानो पहनने के कपड़ों में कॉटन का इस्तेमाल अब समाप्त हो जाएगा लेकिन अब लोग दोबारा कॉटन की ओर लौट रहे हैं। नायलॉन की साड़ी और पॉलिएस्टर के कपड़े अब गंवई होने की निशानी माने जाते हैं।

तमाम तकनीकी नवाचारों को आधुनिकता और प्रगति का उदाहरण माना जाता है जो कभी पीछे नहीं पलटते लेकिन इतिहास पर करीबी नजर डालें तो पता चलता है कि यह बात हमेशा सही नहीं होती। कीटनाशकों, खासतौर पर डीडीटी का इस्तेमाल भी ऐसा ही एक आधुनिकीकरण था जो शुरू हुआ, दशकों तक फला-फूला और उसके बाद उसका पराभव हुआ।

स्विटजरलैंड के एक केमिस्ट पॉल हर्मन मुलर ने दूसरे विश्वयुद्ध से ऐन पहले डीडीटी का अविष्कार किया था। उस वक्त इसे टाइफस और मलेरिया जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों का प्रसार रोकने वाला माना जाता था। युद्ध के बाद इसे जादुई रसायन कहकर पुकारा जाने लगा। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 20 वर्ष की अवधि में लाखों टन डीडीटी का उत्पादन हुआ और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र के कीटों पर नियंत्रण करने में किया गया। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डीडीटी को दुनिया भर में मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनाया और यह अनुशंसा भी की कि मामूली मात्रा में डीडीटी लोगों के घरों में इस्तेमाल करने से उन मच्छरों से निजात मिलेगी जो मलेरिया पैरासाइट के वाहक होते हैं।

भारत में जब यह अभियान शुरू हुआ तब हर वर्ष मलेरिया से करीब 5 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। अगले 10 वर्ष में देश में मलेरिया से होने वाली मौतों का सिलसिला थम सा गया। इसके बाद तो कृत्रिम कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल को वैज्ञानिक प्रगति की तरह देखा जाने लगा। इसके बाद आई रेचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। इस पुस्तक ने बताया कि कैसे एक बार डीडीटी का छिड़काव किए जाने के बाद यह पर्यावरण में बना रहता है और कैसे खाद्य शृंखला में यह एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में पहुंचता हुआ उन्हें नष्ट करने का काम करता है। इस पुस्तक को पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके चलते अमेरिका तथा अन्य सरकारों ने सन 1972 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। डीडीटी का इस्तेमाल खत्म होने पर मलेरिया ने फिर से वापसी की और एक बार फिर लाखों लोग इसकी वजह से मरने लगे। इनमें ज्यादातर अफ्रीकी देशों के बच्चे थे। डीडीटी और ऐसे ही अन्य कृत्रिम रसायन दोबारा इस्तेमाल होने लगे हैं लेकिन कार्सन के आंदोलन ने पर्यावरण आंदोलन को गति प्रदान कर दी थी और यही कारण था आने वाले दिनों में जैविक खानपान का उदय हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं जटिल तकनीकी और सामाजिक प्रक्रिया भी नई तकनीक के उदय और उसके पराभव में अपनी भूमिका निभाती है इससे सबक सीखते हुए यह आवश्यक है कि हम उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पड़ताल करें जिनके माध्यम से प्रिंट मीडिया संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा है।

प्रिंट मीडिया को पहला झटका सन 2000 के दशक के आरंभ में लगा था जब इंटरनेट अपनी राह बना रहा था। उस वक्त इंटरनेट वेबसाइट वैवाहिक विज्ञापन, नौकरी, यात्रा और किराये के मकानों के विज्ञापन निःशुल्क दे रही थीं। इससे अखबारों और पत्रिकाओं के वर्गीकृत विज्ञापन कम होने लगे जो उनकी आय का कम से कम आधा हिस्सा प्रदान कर रहे थे। चूंकि वेबसाइट ये विज्ञापन निःशुल्क दिखा रही थीं इसलिए जल्दी ही इन्हें ग्राहक भी मिले और इसके साथ ही ऐसे वेंचर कैपिटल फंड सामने आए जो इन इंटरनेट मीडिया वेंचर को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार थे। यह सिलसिला आज तक जारी है।

दुनिया भर में समाचार पत्र-पत्रिकाओं का स्वामित्व और प्रबंधन उनके मालिकों के परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में है जिनके पास ऐसी तकनीकी काबिलियत नहीं है कि वे कुछ नवाचार कर सकें।

वे कौन सी सामाजिक शक्तियां हैं जो शून्य लागत वाली पूंजी तैयार करती हैं और जिसे दुनिया भर में लगाया जाता है? यकीनन इसका मूल स्रोत अमेरिका है जहां अत्यधिक प्रभावशाली वित्तीय सेवा समुदाय लॉबीइंग करता है और इस दलील के साथ करीब शून्य ब्याज दर वाली व्यवस्था कायम करता है कि इस ब्याज दर पर कारोबारों को पूंजी सस्ती मिलती है और नए रोजगार तैयार होते हैं। यह बात सच्चाई से दूर है। छोटे कारोबारों के मालिकों को कभी बैंक से पूंजी नहीं मिलती। उन्हें पूंजी किसी पूंजीवादी से मिलती है जो बदले में उनके कारोबार में हिस्सेदारी लेगा।

यह अवधारणा इंटरनेट को एकदम अलग दिशा में ले गई और इसने उसे वित्तीय समुदाय के हाथ का खिलौना बना दिया जिससे वे मनचाहे ढंग से खेलने लगे। बहरहाल, एक मौजूदा अवधारणा जो मुझे चकित करती है वह है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पुस्तकों और वेबसाइटों का रुख। मैं इन दोनों का ग्राहक हूं। जब एक नई प्रोग्रामिंग तकनीक उभरती है तो उन्हें बनाने वाले अपनी तथा अन्य वेबसाइटों पर कुछ उसके बारे में कुछ ललचाने वाली जानकारी डाल देते हैं। उनकी पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप सलाहकार के रूप में उनकी सेवा लेंगे या भुगतान करके उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन या ऑफलाइन शामिल होंगे। या फिर उनके द्वारा लिखी गई किताब खरीदनी होगी जिसका मूल्य कम से कम 35 डॉलर तो होता ही है।

तो क्या प्रिंट मीडिया जगत को अपने लिए किसी रेचल कार्सन की प्रतीक्षा है? या फिर वह किसी ऐसे नए उद्यमी की प्रतीक्षा में है जो इस उद्योग में नवाचार लाएगा?

हमारी प्रकृति बची तभी बचेगी ये दुनिया

भावना मासीवाल

आधुनिक विकास नीतियों ने पूंजी के संरक्षण को बढ़ावा दिया; पूंजी के संरक्षण ने उपनिवेशवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। इसी ने प्राकृतिक संपदा पर अधिकार के प्रश्न को बढ़ावा दिया। फिर प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और स्वामित्व के इसी प्रश्न ने हिंसा को वैश्विक धरातल पर शक्ति का सबसे बड़ा हथियार बना दिया।

जंगल, पेड़, पानी और प्रकृति से ही जीवन बना है। बिना इसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति जीवन है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति है तो जल, जंगल और जमीन है। जल, जंगल, जमीन है तभी मनुष्य का जीवन संभव है। प्रकृति ही है जो अनगिनत जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों, विभिन्न संसाधनों, जैविक-अजैविक घटकों का पोषण करती है। वही है जो इन सभी में खुद को अधिक शक्तिशाली समझने वाले मनुष्य को हवा, जल, भोजन आदि देती है। प्रकृति पर आश्रित होना ही मनुष्य को उसके खुद को सर्वशक्तिशाली समझने के अहसास को कम करती है। क्या कभी हमने सोचा है कि जिसने हमें जीवन दिया, प्राण वायु के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल का आधार नदियां, भोजन और आवास के लिए जंगल और फलों, अनाजों और फसलों का स्वामी बनाया, जीवन को जीने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, उसे बदले में हमने क्या दिया? सिर्फ अपनी आवश्यकता, शौक और शक्ति प्रदर्शन के लिए वनों को काट डाला, नदी का रुख बदल दिया। हवा जो इस चराचर जगत की जीवनदायनी और प्राण है, उसे विषैला बना दिया, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हुए प्रकृति में असंतुलन की स्थिति को जन्म दिया। क्या कभी मनुष्य ने इस पर विचार किया कि प्रकृति ने उसे जो अनमोल धरोहर प्रदान की है उसकी इतनी दयनीय हालत क्यों है? वह तो लालसाओं की होड़ में इस कदर अंधा होकर दौड़ रहा है कि पीछे मुड़ कर अपनी जीवनदायिनी प्रकृति को देखना तक नहीं चाहता है। वह भूल गया है कि जल, हवा, नदी, पहाड़, पठार, जंगल आदि प्राकृतिक तत्त्वों से ही उसका अस्तित्व है। इन सबके अभाव में जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।

मनुष्य भली-भांति इस बात से परिचित है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं भी जीवन संभव नहीं है। फिर भी वह लगातार इसकी संभावनाएं तलाश रहा है। मनुष्य की चंद्रमा से लेकर अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करना इसका प्रमाण है। वह जानता है कि प्रकृति के विविध संसाधनों का उसने अपनी आवश्यकता से अधिक अंधाधुंध उपभोग किया है, जिसके कारण प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। मनुष्य की इसी उपभोग की नीति ने प्रकृति को विनाश के छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है।

प्रकृति में असंतुलन के कारण सामाजिक परिदृश्य भी बहुत तेजी से बदल रहा है। गांव कस्बों में बदल रहे हैं, अनावृष्टि और अतिवृष्टि से खेतों की फसल नष्ट हो रही है, किसान अब किसानी छोड़ कर मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। यह सब प्रकृति में बदलाव के कारण भी हो रहा है। मगर मनुष्य कहां अपनी खामियों को स्वीकार करता है! वह गांव से अधिक शहरों का हिमायती है। उसके लिए विकास का नाम शहर है। इसी कारण गांव नष्ट हो रहे हैं। हम विकास में गांवो को साथ लेकर चलने की अपेक्षा गांव को शहर बनाना चाहते हैं। अब तक प्रकृति से मनुष्य का तादात्म्य बनाए रखने वाले गांव भी अब शहर की तरह सीमेंट की बहुमंजिला इमारतों में बदल रहे हैं और प्रकृति का सान्निध्य छोड़ वे भी विकास की अंधी दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं। इसे गांव की मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वे भी आधुनिक कहे जाने वाले संसाधनों के साथ जीना चाहते हैं। जिसके कारण एक तरफ शहरों की ओर पलायन बढ़ा है तो दूसरी तरफ गांव अब शहर में तब्दील होने लगे हैं। गांवों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन स्थानीयता की नीति के अभाव से उपजा है। वर्तमान समय में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार का अभाव पलायन का मुख्य कारण बन कर उभर रहा है। संकट के इस दौर में बड़ी संख्या में मजदूरों का मजबूर होकर शहरों से गांव वापस लौटना इसी पलायन की त्रासदी का हिस्सा है।जहां शहरों ने उनके श्रम की अवहेलना और उनका अवमूल्यन कर उन्हें वापस गांव जाने पर मजबूर कर दिया। पूंजीवादी नीतियों में गांव के गांव उजाड़ कर उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। विकास के नाम पर धरती का ज्यादातर हिस्सा सीमेंट से पाट दिया गया। नदियां नाले का रूप लेकर सूख रही हैं। इसका भयानक प्रभाव बदलते पर्यावरण पर देखा जा सकता है।

आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में जल, जंगल और जमीन को बचाने का संघर्ष चल रहा हैं। यह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक धरोहर है। अफसोस की बात है कि ये वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली ताकतों के हाथों में हैं, जो निजी हितों के लिए इनका दुरुपयोग कर रही हैं। दरअसल, प्रकृति ही है जो अपने भीतर इतनी विविधताओं को जीवित रख सकती है। अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो विविधताओं से भरा हुआ यह खूबसूरत जीवन भी नष्ट हो जाएगा। जैव विविधताओं से भरी इस पृथ्वी में प्रत्येक जीव का प्रकृति को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह एक प्रकार का संतुलन चक्र है। अगर यह बिगड़ता या टूटता है तो मनुष्य जीवन भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति के साथ तादात्म्य बना कर आगे बढ़े। वह विकास की अंधी दौड़ का हिस्सा बनने की अपेक्षा प्रकृति के साथ विकास की नई नीतियों का निर्माण करे, ताकि मनुष्य के साथ ही प्रकृति के भीतर रहने वाले सभी प्राणी भी विकास में उसके सहयोगी बन सकें।

बाल मजदूरी बढा देगा कोरोनावायरस

अनुमान है कि कोरोनावायरस से आया आर्थिक संकट बाल मजदूरों की संख्या में इजाफे का कारण बनेगा। इससे पहले 2000 से लेकर अब तक बाल मजदूरों की संख्या में लगातार कमी

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोनावायरस लाखों बच्चों को बाल मजदूरी के दलदल में धकेल देगा। जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबरः अ टाइम ऑफ क्राइसिस नामक यह रिपोर्ट 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर जारी की गई है

रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद यह पहला मौका है कि बाल मजदूरों की संख्या में इजाफा हो रहा है पिछले 20 वर्षों से दुनिया भर में किये जा रहे अथक प्रयासों के चलते बाल मजदूरों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी पर कोरोनावायरस के चलते यह जो आर्थिक संकट आया है उससे बदलाव की इस दिशा में परिवर्तन हो सकता है यदि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2000 में करीब 24.6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे यह संख्या 2017 में घटकर 15.2 करोड़ रह गई थी पर इसके बावजूद इनमें से करीब आधे 7.3 करोड़ बच्चे उन कामों को कर रहे थे जिनमें खतरा ज्यादा है 17 सालों की इस अवधि में करीब 9.4 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त हो गए थे पर नई रिपोर्ट में बाल मजदूरों के फिर से बढ़ने का अंदेशा जताया गया है।

जलवायु परिवर्तन से महासागरों में बढ़ेंगे तूफान

यदि वैश्विक उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो व्यापक समुद्री क्षेत्रों में चरम लहरों की आवृत्ति और परिमाण में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। यह अध्ययन साइंस एडवांसेज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है इसके विपरीत, शोधकर्ताओं ने पाया कि उन जगहों पर ये घटनाएं काफी कम होगी और लहरों में भी वृद्धि नहीं होगी, जहां जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हों।

दोनों परिदृश्यों में, चरम लहरों में परिमाण और आवृत्ति में सबसे बड़ी वृद्धि दक्षिणी महासागर में होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के शोधकर्ता प्रोफेसर इयान यंग ने चेतावनी दी है कि अधिक तूफान और चरम लहरों के परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और इससे जानमाल को नुकसान होगा।

कृषि अध्यादेश से छोटे किसानों को कितना लाभ होगा?

कृषि क्षेत्र में दशकों पुरानी सुधार मांग को मानते हुए सरकार ने अध्यादेश जारी किए हैं लेकिन क्या छोटे-छोटे टुकड़े पर खेती करने वाले किसानों का इससे लाभ हो पाएगा

मुरलीधर

पिछले दिनों सरकार ने कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए कृषि मंडियों के बाहर अपनी फसल बेचने और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग को लेकर किसानों के लिए अध्यादेश जारी किए थे। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के जरिए किसानों के लिए रेगुलेटरी व्यवस्था को उदार बनाया गया था। शुक्रवार 5 जून को सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े दो अध्यादेश अधिसूचित किए गए थे। अध्यादेश के मुताबिक किसानों को अपनी पसंद के बाजार में उत्पाद बेचने की छूट मिलेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, "कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत किसान अपनी पसंद के बाजार में उपज बेच पाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि किसानों को फसलों का बेहतर दाम मिलेगा।

एक और अध्यादेश "मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी अधिसूचित किया गया है। इस अध्यादेश के तहत किसानों को एक राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा। जिससे कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातकों और किसानों के बीच पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट होगी। सरकार का कहना है कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या बढ़ेगी। महाराष्ट्र के अमरावती के किसान संदीप रोडे कहते हैं कि सरकार ने जो कृषि सुधार किए हैं उससे किसानों को जरूर लाभ होगा लेकिन वह साथ ही कहते हैं कि जो सरकार ने किया है वह ठोस नहीं है। रोडे कहते हैं, "निश्चित तौर पर सरकार के फैसलों का किसानों को लाभ होगा। किसान अपनी फसल को खुले बाजार में बेच पाएगा और बाजार में

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे दाम अच्छा मिलेगा।

रोडे कहते हैं कि सरकार इन सुधारों को कैसे लागू करवाती हैं, यह देखना पड़ेगा। रोडे का सुंयुक्त परिवार एक सौ से अधिक एकड़ की जमीन पर कपास, ज्वार, हल्दी, तूर, सोय की खेती करता है। रोडे के मुताबिक, "लेकिन अब जमीन परिवार के सदस्यों के बीच बंट चुकी है और साल दर साल किसानी करने वालों को लाभ कम होता जा रहा है। महाराष्ट्र किसान पुत्र आंदोलन के अमर हबीब कहते हैं, "सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर फैसला किया है वह सही है लेकिन यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने अनिच्छा से यह काम किया है। कोरोना वायरस की वजह से देश की जो हालत बिगड़ी है और अर्थव्यवस्था का जो हाल है वह देखते हुए सरकार ने मजबूरी में यह कदम उठाया है। हबीब कहते हैं कि कृषि भूमि सीलिंग कानून की वजह से देश बर्बाद हो चुका है। हबीब कहते हैं, "देश के 85 फीसदी किसान दो एकड़ कृषि भूमि के नीचे है।" सीलिंग कानून के तहत हर राज्य अपने हिसाब से कृषि भूमि की सीमा तय करता है। हबीब कहते हैं, "जमीन के छोटे टुकड़े के साथ किसानों का जीना नामुमकिन जैसा है। छोटे जमीन वाले किसान ही तो शहर की ओर आए थे और अपना पेट पाल रहे थे, लॉकडाउन हुआ तो वे फिर गांव लौट गए।

रोडे के मुताबिक, जो छोटे किसान होते हैं उनको तो बैंक भी कर्ज नहीं देता है और दो से चार एकड़ की जमीन पर साल भर कैसे गुजारा होगा यह अपने आप में सोचने वाला विषय है।" हबीब कहते हैं कि खेती एक नुकसानदायक काम है और इसमें बड़ी कंपनियां नहीं आती है। हबीब का कहना है कि मंडी की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है और बाजार खुलने से किसानों को जरूर लाभ होगा। हबीब के मुताबिक, "यह सरकार तो छह साल से सत्ता में है लेकिन अब क्यों किसान के हित में फैसले ले रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अब किसान याद आ रहे हैं?

पिछले दिनों कृषि मंत्री ने कृषि सुधारों को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन सुधारों को सफल तरीके से लागू करने में सहयोग का आग्रह किया था।

कोरोना योद्धा बधाई के पात्र :सीपी सिंह

रांची :13 जून 2020 को रांची विधायक सीपी सिंह जी ने अपने आवासीय परिसर मे लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंदों के बीच भोजन, मास्क, सैनिटाइजर एवं सैनेटरी पैड वितरण करने वाले 20 महिला, पुरुषों को मोमेंटो, प्रमाणपत्र एवं मैडल भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माही केयर फाउंडेशन के निदेशक आशीष रंजन ने किया। मुख्य अतिथि सीपी सिंह ने समाजसेवियों को सम्मानित करते हुए कहा कोरोना योद्धा बधाई के पात्र हैं उन्होंने गरीब जरूरतमंदों की सेवा कर पुण्यकार्य किया है। आज रोटी बैंक के महिला कोऑर्डिनेटर बंदना कुमारी एवं राकेश रंजन को बेस्ट कोरोना वॉरियर्स अवार्ड, पूजा वेदिया एवं राधा शर्मा को ग्रेट अचीवमेंट अवार्ड सहित अनिता कुमारी, पूनम जायसवाल, शिव किशोर शर्मा, शीला साहू ,कुमुद झा, नीलम शर्मा, सुनीता चौधरी, पायल सोनी, पिया बर्मन , डॉक्टर अनुज कुमार पटेल, ममता साहू, नेहा कुमारी, खुशबू पटेल, आर भारती, आदि को मुख्यअतिथि सीपी सिंहजी ने अपने हाथों सम्मानित कर हौसला बढ़ाया।

महर्षि सेवा संस्थान और मनोहर लाल समृति के सदस्यों ने रक्तदान किया

रांची : महर्षि सेवा संस्थान और मनोहर लाल समृति के सदस्य सुनिल कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी सदस्यों के साथ मिलकर सदर ब्लड बैंक में रक्तदान किया। लोकडाउन में रक्त की कमी को देखते हुए आज के शुभ अवसर पर रक्तदान किया गया ताकि जरूरतमंद को समय पर रक्त की पूर्ति हो सकेगी। सुनिल जी ने सर्वप्रथम आँचल शिशु आश्रम में बच्चों के बीच मिठाईयाँ और आश्रम के लिए सुखा राशन(चावल, दाल, आटा, तेल, आलू, नमक) का वितरण किया। इस अवसर पर संस्थान के जितेन्द्र शर्मा, सुनिल कुमार, राजीव गुप्ता,मनोज, सौरभ, गुंजन गोपी, श्याम, के साथ के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

गरिबों को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्यः हेमा दुआ

रांची :10 जुन 2020 को ओशनिक ग्रुप अरगोड़ा के निदेशक हेमा दुआ ने पहाड़ी मंदिर, माउंट मोटर गली,दुर्गा मंदिर रातू रोड के सैकड़ो गरीबों एवं जरूरमंद लोंगों के बीच पूडी, खीर, सब्जी, मास्क एवं सैनिटाइजर बांटी । इस मौके पर ओशनिक ग्रुप के चेयरमैन राज वर्मा, पंकज कुमार ,अभिनव गिरीश ,हर्षिता श्रीवास्तव, बबीता जी आदि मौजूद थे। बबीता जी एवं हर्षिता श्रीवास्तव ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक जानकारी दी,वही हेमा दुआ ने कहा गरीब, जरूरतमंदो को भोजन देना सबसे बडा पुण्य है साथ ही लोगो को सामाजिक दूरी पालन करने की अपील की। कार्यक्रम की समाप्ति जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि के अवसर पर गरीब, जरूरतमंदो के बीच आवश्यक सामग्री वितरण करने की शपथ लेकर कि गई।

उपायुक्त अपने जिलों में बीज वितरण का काम शुरू करायें :बादल पत्रलेख

- प्रखंड स्तर पर खुलेंगे वेजफेड के आउटलेट
- पलामू में लगेगा स्ट्राबेरी प्रोसेसिंग प्लांट
- किसानों को राहत देने के लिये बनेगा फसल राहत कोष
- एक सप्ताह के अंदर ओलावृष्टि और साइक्लोन से हुए क्षति का रिपोर्ट भेजें
- पंचायत स्तर पर मछली पालन और डेयरी के स्किल ऑफ फाईनेंस की व्यवस्था करेगी सरकार
- 20 लाख किसानों को केसीसी से लिंक कराने का लक्ष्य
- जेएमएफ से जुड़े किसानों को तीन लाख तक का मिलेगा लोन
- निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की स्टेटस रिपोर्ट दें सभी जिला
- मेधा डेयरी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर जोर

संवाददाता

रांचीः राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी जिला के उपायुक्तों को निदेश दिया है कि किसानों और माइग्रेंट मजदूरों के उत्थान तथा उन्हें रोजगार देने के सरकार के मंसूबों को पूरा करने के लिये मिशन मोड में काम किया जाये। उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी और फिशरी से जुड़े किसानों को सरकार की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निदेश दिया कि बीज वितरण का कार्य तीन दिनों के अन्दर जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रारंभ कराया जाये ताकि किसानों को इसका ससमय लाभ मिल सके। वह आज नेपाल हाउस में सभी जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा कर रहे थे।

बादल पत्रलेख ने कहा कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के दौरान जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों ने बेहतर काम किया है और लगभग सभी प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग और कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की जवाबदेही काफी बढ़ गयी है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट मजदूरों को पंचायत स्तर की को-ओपरेटिव सोसाइटी से जोड़े ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। कृषि, पॉल्ट्री और डेयरी के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि ओलावृष्टि और साइक्लोन से हुए क्षति का रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। मंत्री ने सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी कार्यक्रमों में मेधा डेयरी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर फोकस किया जाये ताकि दुग्ध उत्पादन से जुड़े कृषकों को लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही किसान राहत योजना की शुरूआत करने जा रही है और इसके लिये 100 करोड़ के बजट का भी उपबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की राशि किसानों को ससमय नहीं मिल पाती थी जिस वजह से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते तीन सालों में फसल बीमा के लिये इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार ने 477 करोड़ रूपये प्रीमियम का भुगतान किया था लेकिन किसानों को क्षतिपूर्ति मात्र 77 करोड़ रूपये की ही दी गयी और कंपनियां अपनी जवाबदेही से बचती रही हैं। लेकिन राहत योजना से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को 2018 में सूखे के दौरान क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है उसकी रिपोर्ट भेजी जाये ताकि विभाग तत्संबंधी कार्यवाही कर सके। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राहत कोष की राशि बढ़ायी जायेगी। सरकार राज्य में कृषि नीति भी तैयार कर रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में करीब 38 लाख किसान हैं जिनमें से मात्र 18-19 लाख किसानों के पास ही केसीसी कार्ड है। अतः केसीसी से वंचित किसानों को जल्द से जल्द केसीसी से लिंक किया जाये। उन्होंने कहा कि परंपरागत केसीसी में पहली बार मेधा डेयरी फार्म से जुड़े किसानों को तीन लाख रूपये तथा अन्य को 1.6 लाख रूपये का लोन बिना गारंटी के बैंकों के द्वारा दिया जाना है जिसका कार्यान्वयन उपायुक्त बैंकों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करें। बादल पत्रलेख ने कहा कि 16 जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण का काम होना था लेकिन कई जिलों में अभी तक काम प्रारंभ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ और सरायकेला में भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जायेगा। सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास नहीं हुआ वहां इसी महीने शिलान्यास कराने की तैयारी करें। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी प्रखंडों में वेज फेड के आउटलेट खोले जायेंगे ताकि किसानों में अपनी सब्जी बेचने के लिये लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पलामू उपायुक्त ने बताया कि 500 हेक्टेयर में पहली बार जिले में स्ट्राबरी की खेती की जा रही है अगर पलामू में इसका एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हो जाता तो किसानों को फायदा होता। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव भेजा जाय जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण कर काम शुरू कराया जायेगा। साथ ही जामताड़ा में काजू के प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कराने की बात कही।

कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने सभी उपायुक्तो को निदेश दिया कि बीज वितरण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि योग्य किसानों तक बीज पहुंचे साथ ही बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने निदेश दिया कि सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकरी और राष्ट्रीय बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि बीच का वितरण सही समय पर हो सके।

राज्य में हर मजदूर को काम देंगे : मुख्यमंत्री

रांची : हर राज्य के विकास में झारखंड के कामगारों का अहम योगदान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉक डाउन के पहले तक सरकार को यह मालूम तक नही था कि यहां के कामगार लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों में काम कर रहे है ' यहां के कामगारों ने देश के सभी राज्यों के विकास में अहम योगदान निभा रहे हैं और यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है । मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में सभी वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम में सरकार जुट गई है ' चाहे यहां लौट कर आए प्रवासी मजदूर हों या फिर दूसरे राज्यों के मजदूर, जो यहां काम कर रहे हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है ' उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ' इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है । मुख्यमंत्री की मौजूदगी में श्रम विभाग और सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधि के बीच टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टी ओ आर) पर हस्ताक्षर किए गए ' जिसमें कामगारों के स्वास्थ्य ,सुरक्षा कल्याण और वेतन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बेहतर होने की गारंटी दी गई है।

एसोचैम का अपरेंटिसशिप पर वेबिनार

रांची : 14 जून को एसोचैम ने संगठनों और व्यक्तियों को अपरेंटिसशिप के लाभों के बारे में चर्चा करने और लाभ उठाने के बारे में अपरेंटिसशिप पर एक वेबिनार का आयोजन किया। अप्रेंटिसशिप उद्योगों में रोजगार के के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए तैयार करना है। अप्रेंटिसशिप में कार्य-एकीकृत प्रशिक्षण शामिल है, जिसे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और वितरित किया गया है, या तो उद्योग परिसर में या प्रशिक्षण साथी द्वारा सुगम बनाया गया है। प्रशिक्षण के बाद, अधिकांश प्रशिक्षु कर्मचारियों के रूप में अवशोषित हो जाते हैं और अपने चुने हुए करियर में बढ़ते रहते हैं। इस वेबिनार का दायरा उद्योग और युवा रोजगार के मुद्दों से जुड़े कौशल-घाटे की पृष्ठभूमि में अप्रेंटिसशिप और एनएपीएस के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके उद्योग के लिए कुशल श्रमशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण सबसे कुशल तरीकों में से एक है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के बाद व्यक्तियों को नियमित रोजगार के समय आसानी से औद्योगिक वातावरण के लिए अनुकूल कर सकते हैं। एनएपीएस योजना के माध्यम से सरकार से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसके माध्यम से 1500 रू प्रति उम्मीदवार प्रति महिने प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर एसोचैम के क्षेत्रीय निदेशक भरत जायसवाल ने स्वागत भाषण दिया प्रख्यात विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और लोगों को अप्रेंटिसशिप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

मानसून की दस्तक: किसान अब धान बीजस्थली की तैयारी करें

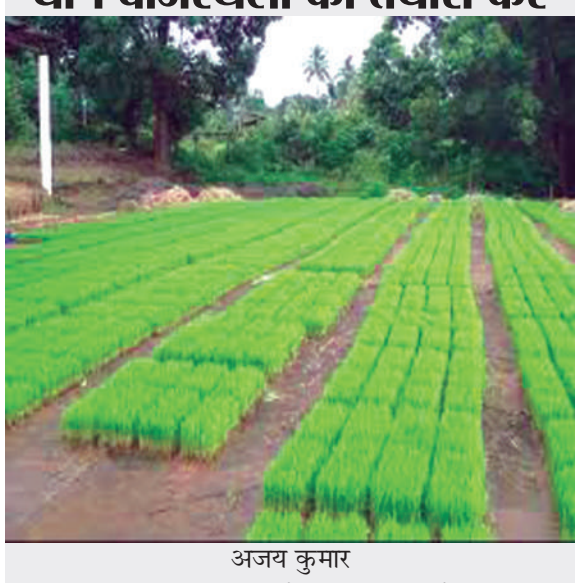

अजय कुमार

रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के धान फसल विशेषज्ञ डॉ कृष्णा प्रसाद ने अगले 5 दिनों के संभावित वर्षा पुर्वानुमान को देखते हुए किसानों को धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीजस्थली (नर्सरी) की तैयार करने की सलाह दी है। उन्होंने किसानों को 3 - 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः तीन - चार किस्तों में बीजस्थली (नर्सरी) में बीज बोने को कहा है। बीज नर्सरी के कार्य 25 जून तक पूरा कर लें। उनका कहना है कि रोपा के समय कादो किया जाता है और ऊंची-नीची जमीन रहने के कारण अलग - अलग खेतों में अलग -अलग समय पर पानी जमा होता है। प्रतिकूल मौसम में धान रोपा अवधि के दौरान उपयुक्त बिचड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है।

एक एकड़ में रोपा के लिए किसान 16 से 18 किलो बीज (बीजस्थली) की आवश्यकता होती है। समय पर बोआई के लिए लंबी अवधि (140-145 दिनों) वाली धान किस्मों जैसे राजश्री , स्वर्णा (एमटीयू -7029), संभा महसूरी (बीपीटी - 5204) तथा उन्नत संभा महसूरी किस्मों का प्रयोग करें। वर्षापात में देरी या कमी होने से कम अवधि वाले किस्मों का चयन करें। बीजस्थली में 100 किलो कम्पोस्ट, 2।5 किलो यूरिया, 6 किलो एसएसपी तथा 1.5 किलो पोटाश प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। निचली जमीन में रोपा के लिए लंबी अवधि वाले किस्म का चुनाव दोन -1 खेत के लिए तथा मध्यम अवधि वाले किस्म का चुनाव दोन -2 खेतों के लिए करें।

हरी खाद फसल की खेती : लागत में कमी, भूमि की उर्वरता व उपज बढ़ोतरी में मददगार

संवाददाता

रांची:भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली के सौजन्य से झारखण्ड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) के माध्यम से जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल (निकरा) नामक परियोजना का संचालन 7 वर्षो से किया जा रहा है। इस केंद्र को परियोजना अधीन अंगीकृत निकरा ग्राम में जलवायु अनुरूप कृषि तकनीकों का प्रदर्शन उत्साहजनक एवं सकारात्मक परिणाम मिले है।

केवीके द्वारा जिले के मुसाबनी प्रखंड के निकरा गांव लावकेशरा, पाथरगोरा एवं बारूनिया में 4 वर्षो से गाँव तालाबों के आस-पास के करीब 15 हेक्टेयर भूमि में कुल 45 आदिवासी किसानों की खेत में हरी खाद फसल ढैंचा का प्रत्यक्षण कराया गया। इस खेती से किसानों के 15 हेक्टेयर भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी देखी गई है। खेती से पहले मिट्टी जाँच में भूमि में उपलब्ध नेत्रजन, स्फूर एवं पोटाश की औसत मात्रा क्रमशः 350, 30 व 184 किलो/ हेक्टेयर पाई गई थी। 4 वर्ष के बाद जो बढ़कर क्रमशः 443, 37 व 295 किलो/ हेक्टेयर हो गई है। इस खेती से भूमि की अम्लीयता में भी सुधार पाया गया है। पहले भूमि का पीएच मान 5.10 था और अब पीएच मान 6.95 पाया गया है। इसीतरह भूमि में जैविक कार्बन की स्थिति में भी सुधार देखा गया है। हरी खाद फसल ढैंचा की खेती के बाद इन खेतों में धान की औसत उपज में 47 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। पहले किसानों को धान की खेती में 1.30 रूपया खर्च कर 1.90 रूपया की आमदनी होती थी। हरी खाद फसल की खेती के बाद धान की खेती से किसानों को 1.0 रूपया खर्च कर 2.80 रूपया का लाभ प्राप्त हो रहा है।

इस तकनीकी प्रदर्शन में धान की खेती में उ-वर्रक व सिंचाई लागत में कमी, कम लागत से अधिक उपज और आमदनी एवं भूमि स्वास्थ्य में सुधार को देखकर आस-पास के गाँवो के करीब 150 से अधिक किसानों ने 110 हेक्टेयर भूमि में इस वर्ष

हरी खाद फसल की खेती तकनीक को अपनाया है। बीएयू मृदा वैज्ञानिकों का कहना है कि कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते व्यवहार से खेती लागत में बढ़ोतरी हो रही है। इससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति घटती जा रही है। किसान ग्रीष्म ऋतु में हरी खाद फसल की खेती से आगामी खरीफ फसल का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। ढैंचा और सनई हरी खाद की एक सहायक फसल है। इसके जड़ों में मौजूद राइजोबियम जीवाणु,जो मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। किसान अप्रैल से मई महीने में बुवाई कर सकते है।

केवीके के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ आरती बीना एक्का बताती है कि हरी खाद फसल की खेती में न्यूनतम खर्च एवं सिंचाई की जरूरत होती है। इस-ाकी खेती से प्रति हेक्टेयर करीब 10-15 टन हरी खाद उपलब्ध हो जाता है और 60-80 किलो नेत्रजन ली जाने वाली फसल को प्राप्त होता है। यह मिट्टी की ऊपजाऊ क्षमता बढ़ाने का एक सस्ता विकल्प तथा इससे किसानों को पशुओं के पोषण के लिए चारा फसल तथा अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलता है।

प्रकृति ही ईश्वर है : अंजना प्रियदर्शनी

रांची : छात्र क्लब मानव कल्याण मंच के प्रदेश संरक्षक ललित चौधरी के शादी के वर्षगांठ के अवसर पर चित्रगुप्त कॉलोनी शिव मंदिर के निकट वृक्षारोपण करते हुए अंजना प्रियदर्शनी ने कहा प्रकृति ही ईश्वर है। पेड़,पौधा, जल, नदी , कुंओं, तालाबों, को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य एवं धर्म है। क्लब के अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा के निर्देशन में सरोवरनगर मुहल्ला में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गरीब, जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, मिक्सचर, बिस्कुट आदि वितरण कर लोगों को घर में रहने, पुलिस, प्रशासन, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्यरूप से अनिता कुमारी, नीलम किरण, शीला साहू, नेहा सिंह, अंजना प्रियदर्शनी, पुनमलाल आदि मौजूद थे।

आसाम के तिनसुकिया गैस कुएं में आग और तेल रिसाव से खेती की जमीन हुई खराब

जगन्नाथ जग्गु

लगभग 14 दिन तक तेल रिसाव के बाद 9 जून को आसाम के तिनसुकिया जिले में इस तेल कुएं में आग लग गई थी असम के तिनसुकिया जिला में बाघजन स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में भयंकर आग के चलते करीब 42 किलोमीटर दूर और डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क से लगते इलाकों में दहशत पैदा कर दी है।

तिनसुकिया जिला में पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ 'ग्रीन विज़न फॉर नार्थ ईस्ट' के बिरेन्द्र कुमार चुटिया ने बताया कि इस दुर्घटना में 1900 से अधिक परिवारों ने अपनी आजीविका गवां दी हैं। साथ ही, डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क और प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी हैबिटैट मगुरी-मोटापुंग बील भी इसकी चपेट में आया है। पर्यावरणीय लिहाज से यह बहुत बड़ा नुकसान है। चूंकि यह एक पर्यटन स्थान भी है, जिसके कारण और अधिक लोगों की आजीविका प्रभावित होनी की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां सब कुछ नष्ट हो चुका है। आग और तेल फैलने के कारण खेती की जमीन हमेशा के लिए खराब हो गई है। हम

यहां अब कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। इसीलिए राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड से हमारी मांग है कि वे हमें अगली पीढ़ी तक के लिए मुआवजा देना चाहिए। हालांकि तेल कंपनी ने अपने घरों से विस्थापित प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपये देने का फैसला किया है।

तिनसुकिया कॉलेज के रसायनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. बिप्लब बनिक कहते हैं कि गैस रिसाव और भीषण आग के कारण विभिन्न प्रकार की गैसों की उत्सर्जन की सम्भावना हैं। मसलन, काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे -जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा। जो स्थानीय लोगों और वन्यजीवों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है और उनके फेफड़ों तक का नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं, तिनसुकिया जिले की लोपमुद्रा तमोली कहती हैं, बाघजन में तेल निकासी स्थल, जहां 14 दिन पहले एक विस्फोट हुआ था, अब भी आग लगी हुई है। 15-20 किलोमीटर दूर तिनसुकिया शहर के लोग भी अपने घरों से आग की लपटें और काला धुंआ देख सकते हैं। वे लोग दहशत में हैं। वह बताती हैं कि जब स्थानीय लोगों ने आशंका जताई थी कि ओआईएल की वजह से यहां आग लग सकती है तो कंपनी के अधिकारियों ने इससे इंकार किया था, लेकिन अब आग लग चुकी है तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। 27 मई को तेल के कुएं से गैस रिसाव के मामला सामने आने के बाद कम्पनी ने सिंगापूर से तीन विशेषज्ञों को बुलाया। वे सभी रिसाव बंद करने की कोशिश ही कर रहे थे 9 जून को विस्फोट हो गया। अब तक रिसाव बंद करने में सफलता न मिलने के कारण तीन अन्य विशेषज्ञों को अमेरिका और कनाडा से बुलाया गया है।

उधर, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक सीएल दास के अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जाँच का आदेश दिया है। जिसमें ओएनजीसी के पूर्व अध्यक्ष बीसी दास और पूर्व निदेशक टीके सेनगुप्ता शामिल हैं।

इसके नियंत्रण के लिए बुआई के 2-3 दिनों बाद खरपतवारनाशी ब्युटाक्लोर 50 ईसी, 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 300-400 लीटर पानी में घोलकर स्प्रयेर से छिड़काव अवश्य करनी चाहिए। इस विधि से खेत की नमी का उपयोग कर आसानी से धान की खेती और मॉनसून में विलंब, अपर्याप्त वर्षापात, असमय व अनियमित वर्षापात की चुनौती से निबटने में मदद मिलती है। प्री-मॉनसून की हल्की बारिश में ही खेत जोतकर क्यारी बनाकर बीज डाल दिये जाते हैं। मिट्टी की नमी से बीज जल्द ही अंकुरित होकर बड़े होने लगते हैं। बाद में औसत बारिश से भी काम चल जाता है। धान करीब माह भर पहले ही पक जाते हैं। पानी की 35 - 40 % तक बचत होती है, उत्पादन लागत करीब 3500 रू।/ हेक्टेयर और पैदावार में 10 % तक बढ़ोतरी होती है। मजदूरों की कमी की दुर्दशा को कम करता है तथा रबी फसलों की खेती समय पर किया जाना आसान हो जाता है। इससे किसान किसान कम लागत में आसानी से अधिकतम शुद्ध लाभ ले सकते है।

फोटो न्यूज

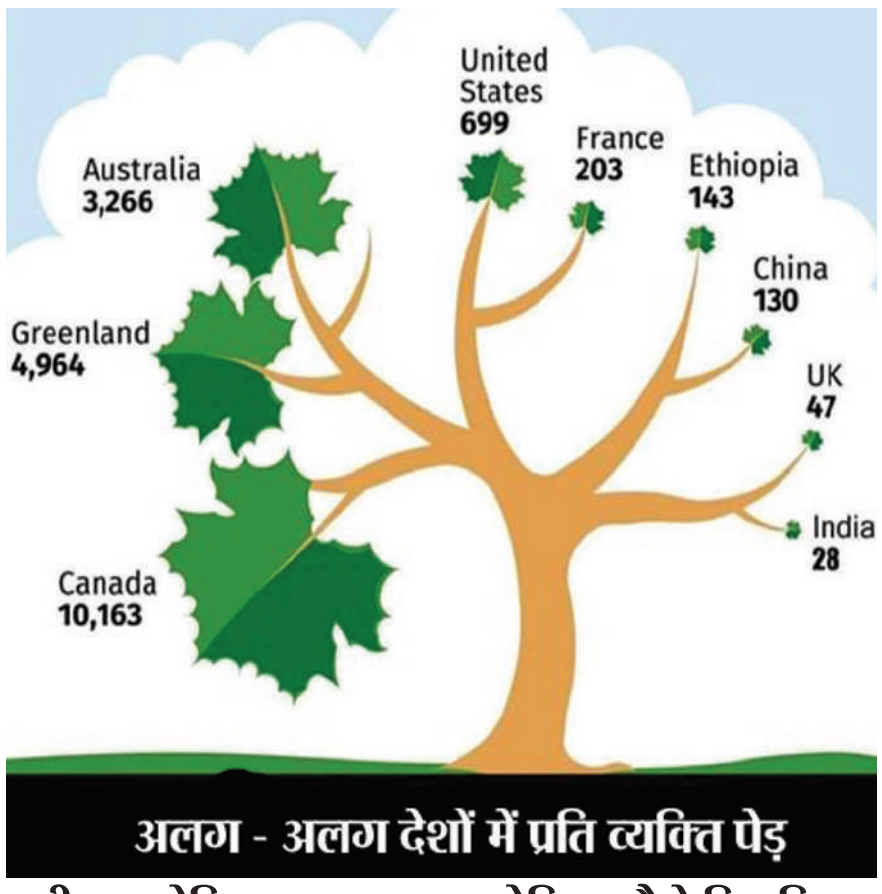

अलग - अलग देशों में प्रति व्यक्ति पेड़

चीन ,अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों का पर्यावरण भी भारत से अच्छा है तभी तो प्रति व्यक्ति पेड़ों के मामले में वो हमसे आगे हैं।

मधुमेह नियंत्रण के लिए योगाभ्यास और अच्छी जीवनशैली

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

जैसा कि हम सब जानते है कि कोई भी चीज अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है , जैसे चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हम मधुमेह कहते हैं ।जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं बनाता है तो इससे खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है ।

डायबिटीज़ या मधुमेह के प्रकार

✓प्री-डायबिटिज़ -जब खून में शुगर लेवल खतरे के निशान के ठीक करीब होता तो इसे प्री-डायबिटीज़ कहते हैं। अपने जीवन-शैली में बदलाव कर के इसे नियंत्रित किया जा सकता है इसे सीमा का डायबिटीज़ भी कहते हैं।

✓टाइप 1 डायबिटीज़ -इस स्थति में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है ये अक्सर अनुवांशिक होता है इसमें इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा ही लेना पड़ता है।

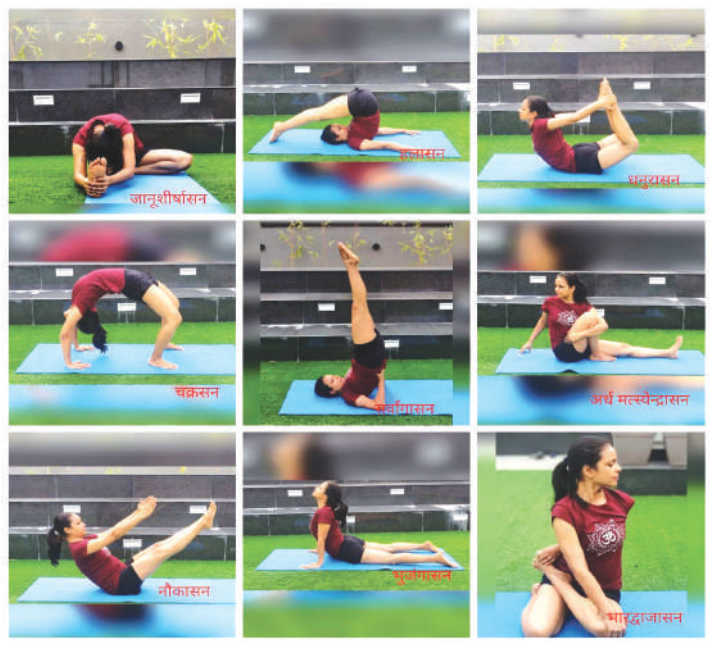

✓टाइप 2 डायबिटीज़-जब शरीर इन्सुलिन तो बनता है परंतु उसकी मात्रा काफी कम होती है, जिससे ब्लड में शुगर का स्तर काफी बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित रहते हैं।

डायबिटीज के लक्षण

✓अचानक या तो वज़न काफी बढ़ जाता है या काफी कम होने लगता है।
✓बार-बार तेज़ भूख लगना भी डायबिटीज़ का लक्षण है।
✓बार बार तेज़ प्यास लगना।
✓बार-बार पेशाब का आना।
✓घाव या चोट जल्दी ठीक न होना।
✓शरीर में झुनझुनाहट का होना।
✓आंखो का कमज़ोर होना।
✓हृदय सम्बंधित रोग होना।
✓त्वाचा सम्बंधित समस्या होना।
✓किडनी से सम्बंधित समस्या होना।

मधुमेह पर नियंत्रण

मधुमेह पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी जीवन-शैली को सही रखनी होगी जैसे कि..

✓ समय पर खाना और सेहतमंद खाना खाना चाहिए।
✓धूम्रपान नहीं करना।
✓तनाव में कम रहना।
✓चीनी का प्रयोग कम करना
✓अच्छी नींद लेना आदि है।
✓योग अभ्यास करना।

योग अभ्यास मधुमेह को नियंत्रित करने में काफी सहायक होता है ।ये पैनक्रियाज को इन्सुलिन बनाने में मदद करता है और रक्त शर्करा स्तर को भी नियंत्रित रखता है। कुछ योग अभ्यास जो मधुमेह के लिए फायदेमंद है।

✓जानूशीर्षासन
✓अर्ध मत्स्येन्द्रासन
✓सर्वांगासन
✓हलासन
✓भुजंगासन
✓नौकासन
✓चक्रासन
✓धनुरासन
✓भुंजगासन

हमेंशा योग की शुरुआत किसी शिक्षक के निरीक्षण मे करें।

हमसे जुड़े. रहने के लिए इंस्टाग्राम पर .फॉलो करें ritusinghfitness.

Tusker Visit

Shilpi Verma

The silent story of the SILENT VALLEY FOREST sent jitters down my spine as I was transponded to years. back when I stayed on the banks of the Mahananda forest reserve. Surrounded by lush green forests and myriad species of flora and fauna ,life was peaceful except few stray incidents of a hyena crossing my path while taking evening walk. But the most captivating visits were those made by herds of elephants sashaying down the road , oblivious to the humans nearby. We had all been given strict intructions or SOP on the does and don'ts on chancing upon a herd. We rushed indoors so as not to disturb them. The males are considered more fierce and females alert about their young ones, who were kept in the middle to prevent them from straying away from the wiser ones. We peeped from the windows of our homes to see their where about…..one had entered our garden! Another in our backyard uprooting precariously planted kitchen garden herbs .The one in the front garden was upturning flower pots and breaking them….all in search of food….their territory had been invaded. Instead of the tall trees and thick canopy stood two story buildings, tarred roads ,cars, children running ,but the moment it was 5.00pm…..it started to get dark as the sun sets early in the East... there would be an eerie silence and kids eagerly awaited visits of tusker families. There seemed to be a mutual understanding….days were ours …late evenings and nights were theirs when they were on the prowl. If ever elders resorted to shooing them away the kids revolted to let them be…in their land …WE WERE VISITORS. Today as the world goes Back to basics with the Pandemic, THE SILENT VALEY FOREST makes us ponder at such cruelty. LET THEM BE WILD …LET THEM BE FREE…THEY HAVE AS MUCH RIGHT AS DO WE.

Author is an student of DJMC Ranchi university, Ranchi

कोरोना के चलते मेडिकल कचड़े में हुई बेतहाशा वृद्धी

अब अपरिचीत न रहा एलोवेरा

हाल के कुछ सालों में एलोवेरा जेल और एलोवेरा के तरह-तरह के सौंदर्य प्रसाधन बाजारों में बहुतायत में आने लगे तभी से लोग इसके पौधों से भी अच्छी तरह से परिचीत हुये।

घृतकुमारी को ही एलोविरा व ग्वारपाठा भी कहते है। यह काँटेदार पत्तियों वाला पौधा है। औषधि की दुनिया में इसे संजीवनी भी कहा जाता है इसमें 18 धातु, 15 एमीनो एसिड और 12 विटामिन मौजूद होते हैं,इसकी तासीर गर्म होती हैं। एमिनो एसिड की प्रचुर मात्रा हमे एलर्जिक रोगों से बचाती है,खून की कमी को दूर करती है । एलोविरा ज्यूस का सेवन शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है वही दिन-भर शरीर में शक्ति व चुस्ती-स्फूर्ति बनी रहती है। एलोवेरा में एंटी बैक्टेरिया और एंटी फंगल गुण के कारण घाव को जल्दी भरता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। बवासीर हो या डायबिटीज गर्भाशय के रोग हो या पेट की खराबी जोड़ों का दर्द हो या त्वचा की खराबी सबका समाधान सुबह खाली पेट लिया जाने वाला एलोविरा ज्यूस बन सकता है।

इसका गूदा या जैल निकालकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल काले, घने-लंबे एवं गंजेपन को दूर किया जा सकता है। रोगों के साथ सौंदर्य निखार में एलोविरा सबसे आगे है वर्तमान बाजार में एलोविरा के हजारो प्रोडक्ट उपलब्ध है जिसमे । एलोविरा जैल, बॉडी लोशन, हेयर जैल, स्किन जैल, शैंपू, साबुन, फेशियल फोम, ब्यूटी क्रीम आदि ।अपने अनुभव ,जानकारी अवश्य शेयर करे ओर अपने घर आंगन में एलोविरा को स्थान दें।

नंदकिशोर प्रजापति कानवन के वाल से

इस भौतिक सुख का कही तो अंत होगा?

अजय कुमार

पर्यावरण हमारे चारों ओर का बाहरी आवरण है। हम जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और सूरज की रौशनी हम तक पहुंच रही है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, सब पर्यावरण का ही उपहार है। यह बहुमूल्य है और यह हमारे भविष्य के लिए भी जरूरी है। सामान्य अर्थ में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व, प्रक्रिया और घटनाओं को पर्यावरण कहा जाता है। यह बहुत व्यापक है। इसमें सूक्ष्म जीवन से लेकर कीटाणु, पशु-पक्षी और पेड़-पौधे आते हैं। पेड़-पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

पांच तत्वों जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश के निर्माण और पोषण में पर्यावरण की केंद्रीय भूमिका है। उसी प्रकार पर्यावरण हमारे जीवन की प्रत्येक घटना से प्रभावित होती है। जीवधारी एवं उसके पर्यावरण के बीच एक अटूट संबंध है। वर्तमान पीढ़ी के जरूरत को पूरा कर सके और भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, ऐसे विकास की जरूरत के लिए पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने में पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए टिकाऊ विकास जरूरी है।

झारखंड जैसे राज्य में जहां एक तिहाई भाग पर जंगल है, वहां अर्थव्यवस्था के विकास की पूरी रूपरेखा को जंगल आधारित किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरत है कि हमारे ज्ञान एवं पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण शिक्षा का चैप्टर शामिल हो। पर्यावरण की जानकारी और उसकी शिक्षा में अंतर है। शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढाने के अलावा सभी समस्याओं का पता लगाने और उसके समाधान पर काम किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जंगल के संरक्षण, गुणवत्ता और संवर्द्धन की व्याख्या की जा सकती है। वर्तमान समय में जरूरी है कि मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बदले उसका संरक्षण करे। पर्यावरण सुरक्षा के बिना टिकाऊ विकास संभव नहीं है। आज हमारा वातावरण दूषित है। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले गैसों के कारण हवाएं प्रदूषित हो रही है, रासायनिक खादों के कारण पृथ्वी मरती जा रही है, कचरे के कारण नदियां दूषित हो रही है और जंगल लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में समूचे समाज को सामाजिक वानिकी से जोड़ना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हमें कचरा एवं प्रदूषित पदार्थों के आत्मसात करने के तरीके खोजने होंगे ताकि उन कचरों से कुछ प्रदूषणविहीन प्रकिया का विकास किया जा सके। कई ऐसे क्षेत्र है, जहां प्रकृति और विकास में कही कोई विरोधाभाष नहीं है। उदाहरण के लिए परंपरागत तरीके जैसे कि जैविक एवं रसायनविहीन कृषि की अवधि न केवल लंबी होगी, बल्कि इससे एक स्वस्थ विकास भी हो सकेगा। परंपरा, प्रौद्योगिकी, सच्चाई और व्यापार ऐसे चार कारक है, जिसको बार-बार पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो जिस कारण से इनका उपयोग किया जाता है, वह अर्थ ही खो देगा।

आधुनिक एवं प्राचीन तरीकों को लगातार पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सभ्यता की दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय हो या भौतिक सुखों के विस्तार से अलग रखने का मामला हो। यह ऐसे पड़ाव है, जहां निर्णय हमें खुद लेना होगा। राज्य तो कभी भी किसी जीवन प्रणाली को समाज पर थोप नहीं सकता है। भौतिक सुख की खोज एवं उसके विस्तार में हम पानी, अन्न, वन और भूमि तथा इसके भीतर सम्माहित सभी खनिजों को खत्म कर अकाल की स्थिति तक पहुंचा गये है।

शहरीकरण के लिए वन कट रहे है, तो कृषि योग्य भूमि लगातार सिकुड़ रही है। आखिर इस भौतिक सुख का कही तो अंत होगा!

केनाइन डिस्टेंपर रोग से मर रहे हैं गिर वन के शेर

ईशान कुकरेती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 जून को एशियाई शेरों की आबादी (2015 और 2020 के बीच 151) में 29 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि का जश्न मना रहे थे, तब ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी से लेकर अब तक गुजरात के गिर लॉयन लैंडस्केप में 92 एशियाई शेरों की मौत हो चुकी है।

कुछ शेर आपस में लड़ कर मर गए और कई कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) की वजह से मर गए। मंत्रालय से जुड़े एक रिपोर्ट की मानें तो जसधर रेसक्यू सेंटर में समिति को दो शेर दिखाए गए, जो सीडीवी से पीड़ित थे। 92 में से 36 शेरों की मौत मई में हुई, जबकि अप्रैल में 24, मार्च में 10, फरवरी में 12 और जनवरी में 10 शेरों की मौत हुई थी। कुछ जानकारों का दावा है कि मरने वालों में 19 शेर, 25 शेरनियां, 42 शावक और 6 अज्ञात शेर शामिल हैं। इनमें से सबसे अधिक 59 शेरों की मौत गिर के ईस्ट डिवीजन, धारी में हुई, जहां 2018 में केनाइन डिस्टेंपर वायरस का प्रकोप हुआ था।

दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2018 में जब सीडीवी का प्रकोप हुआ था, उस महीने 26 शेरों की मौत हुई थी, जबकि मई में उससे अधिक शेरों की मौत हुई।

एशियाई शेरों के विशेषज्ञ एवं भारतीय जैवविविधता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के आंकड़े उपलब्ध कराने वाली गैर लाभकारी संस्था मेटास्ट्रींग फाउंडेशन के सीइओ रवि चेल्लम के अनुसार, गिर लॉयन लैंडस्कैप में शेरों की मृत्यु दर का कोई बेसलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है। मार्च 2018 में गुजरात सरकार ने कहा था कि दो साल में 184 शेरों की मौत हो गई। इस बार पांच महीनों में 92 की मौत हुई है, जबकि 60 की मौत सिर्फ अप्रैल और मई में हुई है। हालांकि, गुजरात वन विभाग ने सीडीवी की उपस्थिति से इनकार किया है। जूनागढ़ वन्यजीव सर्कल के मुख्य वन संरक्षक डीटी वासावदा ने कहा कि गिर में यहां कोई सीडीवी नहीं है। हमने अप्रैल में बेबेसिया और सीडीवी के लिए बड़ी संख्या में नमूनों का परीक्षण करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि सीडीवी का मुद्दा गुजरात सरकार के खिलाफ मीडिया द्वारा उछाला गया है। इसमें कोई सच्चाई

नहीं है। मंत्रालय ने 29 मई को एक समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहायक महानिरीक्षक, मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग के संयुक्त निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के एक पशु चिकित्सक शामिल है। मंत्रालय ने समिति के गठन के साथ ही कहा था कि समिति को जून के पहले सप्ताह में ही क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और शेरों की मौत के संयोग, मृत्यु का कारण पता करना चाहिए। साथ ही, यह भी पता करना चाहिए कि शेरों की मौत को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए।

समिति ने 31 मई और 1 जून के बीच क्षेत्र का दौरा किया और जून के पहले सप्ताह में मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात में शेरों की संख्या की वृद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, सरकार गिर में एशियाई शेरों की मृत्यु की उच्च दर से पूरी तरह से अवगत थी। 10 जून को, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) से दो पेज की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 15वीं एशियाई शेरों की आबादी का अनुमान 5-6 जून को लगाया जाना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे टाल दिया गया। क्या यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया? गुजरात के वन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि गिर में शेरों की मौतों की खबर से ध्यान हटाने के लिए एशियाई शेरों के आंकड़ों का प्रचार किया जा रहा है।

शेरों की मौत की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट सरकार के पास थी, लेकिन इससे ध्यान हटाने के लिए 5-6 जून को लगाए गए अनुमान को बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं कि जो अनुमानित आंकड़ा अभी बताया जा रहा है, वो नियमित प्रक्रिया है। 5-6 जून को जो अनुमानित गिनती की गई, उसे पूनम अवलोकन कहा जाता है। और यह अवलोकन 2014 के बाद से हर महीने गिर में वन विभाग द्वारा किया जाता है। वन विभाग के अधिकारी अपने अपने डिवीजन में गश्त के दौरान शेरों की गणना करते हैं।

रवि चेलम कहते हैं कि गुजरात सरकार पिछले कई सालों से यह बहाना बनाती रही है कि मध्यप्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों का पता नहीं चल पाता है। यह सही है कि यहां सीडीवी अपनी पकड़ बना चुका है और यह एक टाइम बम की तरह है। समझ नहीं आता कि 2103 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, हम दुनिया की एकमात्र एशियाई शेर आबादी को खतरे में क्यों डाल रहे हैं?

E ZONE CARE

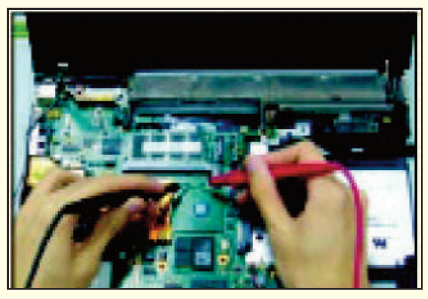

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।